THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) and (b). Yes, Sir. The delay in implementation of major projects and likely cost escalation is as per the annexure.

(c) Slippages have occurred mainly on account of the failure of construction agencies and equipment suppliers to keep to the time schedules. Both SAIL and Government are closely monitoring the performance of implementing agencies who have been asked to augment their resources for speedier execution.

Statement

Scheme	Commissioning date		Estimated cost (Rs in crore)	
	Original	(Likely)	Sanctioned	(Revised)
I *Bokaro Steel Plant :* .	June 1979	July 1983	Rs 947.24 (Mid 1974)	Rs 1,619.33* (April 1982)
(i) 4.0 MT Expn. excluding Cold Rolling Mill (CRM) 4.0 MT with CRM	Dec. 1982	June 1984	(included above)	
(ii) Meghahturburu Iron Ore Project	March 1981	Sept. 1983	51.39 (1st Qtr '77)	116.46* (April '82)
(iii) Captive Power . .	Dec. 1983	Jan. 1984	75.94 (I Qtr '78)	120.84* (IV Qtr 1981)
II *Bhilai Steel Plant :*				
4.0 MT Expn. Phase-I	Sept. 1981	March 1984	937.70 (I Qtr 1974)	1600.5* (IV Qtr '81)
Phase-II . . .	June 1983	Dec. 1984	(included above)	
III *Rourkela Steel Plant :*				
Silicon Steel Project .	Jan. 1981	March 1983	109.73 (I Qtr '76)	154.81* (April '81)
IV *Durgapur Steel Plant :*				
Cpative Power Plant .	June 1983	March 1984	54.91 (I Qtr '78)	82.47 (II Qtr '80)

*Estimates yet to be approved.

Letter of intent of Mopeds

950. SHRI TARIQ ANWAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing:

(a) the number of the proposals received by the Ministry of Industry (SIA) for the issue of letter of intent for the mopeds date-wise and registration number-wise in chronological order during the first six months of 1982;

(b) which of these applicants have been issued the letter of intent or approved by the Licensing Committee;

(c) the number of the proposals which came up for consideration before the Committee for approval but were deferred without assigning any reason;

(d) whether it is also a fact that the proposals that were deferred have not been considered whereas those submitted afterwards and that too by the MRTP and other big companies were not only brought for consideration but were also approved; and

(e) the total capacity for which Government would issue the letter of intent

during 1982, and the details of the applications pending technical scrutiny?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) to (e). During January—June, 1982, 9 applications for the grant of Leters of Intent/Industrial Licences under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, for the manufacture of mopeds were registered in the Secretariat for Industrial Approvals. Out of these, two applications have since been rejected and the remaining seven applications are at various stages of consideration. Cases are never deferred by the Approval Committee without adequate reasons. Licensing Procedures have been streamlined to ensure that all pending applications are considered and disposed of expeditiously as possible. Details of pending applications are not divulged until Government have taken final decisions thereon. Particulars of approval letters, when issued, are published in the 'Monthly Newsletter' brought out by the Indian Investment Centre.

Annual quotas for licensing of capacities for different industries are not fixed. Licensing of capacity depends, among other things, on the demand projections, extent of implementation of the licences/letters of intent already issued with reference to the degree of realisation of the licensed capacity and utilisation of installed capacity, technical soundness of the proposal and capability of the applicant.

साम्प्रदायिक दंगे

951. **श्री कृष्णादत्त सुल्तानपुरी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री गुलाम रसूल कोचक :
श्री उत्तम भाई एच. पटेल :
श्री जी. एम. बनातवाला :
श्री ए. नौलाली हिथादसन नाडार :
श्री राम विलास पासवान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां चालू वर्ष के दौरान साम्प्रदायिक दंगे (राज्यवार) हुए और उनमें कितने व्यक्ति (राज्यवार) मरे ;

(ख) उन दंगों में अन्तग्रस्त समितियों के बारे में क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी से मई, 1982 तक की अवधि के दौरान संलग्न विवरण में उल्लिखित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दू और मुसलमान समुदायों के लोगों के बीच साम्प्रदायिक प्रकार की वारदातें हुई । इन वारदातों में मारे गये व्यक्तियों की संख्या भी उक्त विवरण में दी गई है । तमिलनाडु में हिन्दुओं और ईसाइयों के बीच हुई कुछ और वारदाताओं में 9 व्यक्तियों ने जान गवाई । पंजाब में हिन्दुओं और सिखों के बीच हुई वारदातों में एक व्यक्ति मारा गया ।

(ग) सरकार ने राज्य सरकारों पर इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया है कि साम्प्रदायिक वारदातों की स्थितियों का सख्ती से, तत्परता से तथा कारगर ढंग से मुकाबला किया जाय और इन्हें फिर से होने से रोका जाय। राज्य सरकारों को समय-समय पर विभिन्न उपाय करने का सुझाव दिया गया है जैसे कि स्थानीय आसूचना व्यवस्था का स्तर बढ़ाना; केन्द्रीयकृत कन्ट्रोल कक्ष स्थापित करना; पुलिस की तैनाती को मजबूत करना ; असामाजिक तत्वों के खिलाफ विभिन्न निवारक कार्रवाइयां करना, आग्नेयास्त्रों पर कड़ा नियंत्रण रखना ; अवैध हथियारों तथा गोलाबारूद का पता लगाने के लिए जोरदार उपाय करना ; महत्वपूर्ण उत्सवों तथा समारोहों आदि के अवसरों पर विशेष सावधानी बरतना । साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के वास्ते केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है । असामाजिक तत्वों तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ निवारक कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के उपबंध भी मौजूद हैं । राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनर्गठन किया गया है और 12 नवम्बर, 1980 को इसकी बैठक की गई है । परिषद् ने साम्प्रदायिक